227 क लेख ग्लोबलाइजेशन इक्यान्नवे से ग्यारह तक

227 ख लेख **क्या हम्माम में सब नंगे हैं?**

227 ग लेख युवा संवाद जुलाई ग्यारह का सम्पादकीय

227 घ प्रश्न– आचार्य पंकज, राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यवस्था परिवर्तन मंच, रिषिकेष हरिद्वार

227 च प्रश्न– श्री सत्यमेव गुप्त रूदौली बाराबंकी उत्तरप्रदेश

227 छ प्रश्न– श्री ओमपाल जी मेरठ उत्तर प्रदेश

227 ज प्रश्न– आचार्य पंकज रिषिकेश उत्तराखंड

ग्लोबलाइजेशन इक्यान्नवे से ग्यारह तक

ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है उदारीकरण । भारत ने उदारीकरण की सन इक्यान्नवे से राह पकडी जो आज तक धीरे धीरे सरक रही है। उदारीकरण की शुरूआत मनमोहन सिंह जी ने की थी जो उस समय नरसिंह राव सरकार मे वित्तमंत्री थे और आज प्रधानमंत्री हैं। उदारीकरण का सीधा सा आशय होता है विकेन्द्रीकरण । यह केन्द्रीयकरण तथा अकेन्द्रीयकरण के बीच की स्थिति होती है।। केन्द्रीयकरण का परिणाम होता है सुव्यवस्था और गुलामी । विकेन्द्रीयकरण का परिणाम होता है अव्यवस्था और लोकतंत्र ।अब यह समाज पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा मे जाना चाहता है।

उदारीकरण दो प्रकार का होता है (1) राजनैतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण (2) आर्थिक शक्ति का विकन्द्रीकरण। इक्यान्नवे के पूर्व भारत मे समाजवाद के नाम पर केन्द्रीयकरण था जिसमे राजनैतिक शक्ति भी तंत्र के पास ही इकठ्ठी थी और आर्थिक शक्ति भी । पूंजीपति भी राजनैतिक शक्ति की दया के पात्र थे। तंत्र और लोक के बीच मालिक और गुलाम का रिश्ता था। दोनेा के बोच राजनैतिक शक्ति की असमानता भी असीम थी और आर्थिक शक्ति की भी। किन्तु समाज के अंदर असमानता कम थी । श्रम और बुद्धि के बीच भी इतना फर्क नही था और श्रम वुद्धि और धन के बीच भी फर्क कम था। आम नागरिक संतुष्ट थे क्योकि ऐसी समाजवादी गुलामी को उन्होने अपनो नियति मान लिया था। ज्यादा पंख फडफडाने से पंख कटना निश्चित दिखता था क्योकि आसमान मे उडने की एक निश्चित सीमा निर्धारित थी। सन इक्यान्नवे मे जब ऐसी समाजवादी सुव्यवस्था पर से नेहरू परिवार का पंजा कमजोर हुआ तब नरसिंह राव प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह वित मंत्री बने । मनमोहन सिंह उस समय वित मंत्री मात्र थे। उनकी आर्थिक उदारवाद तक ही सीमाएँ थी । उन्होने राजनैतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण को तो नही छुआ किन्तु आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण का मार्ग खोल दिया । मै नही कह सकता कि उक्त उदारीकरण पर विश्व साम्यवाद की असफलता की घोषणा का कोई प्रभाव था या नहीं किन्तु दोने घटनाएं एक ही कालखंड की है जिसमे गोर्वाचोव ने राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया और भारत आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण तक सीमित रहा।

भारतीय राजनीति का यह इतिहास रहा है कि भारत मे एक चौकडी हमेशा बनी रहती है जो नेहरू परिवार के चारों ओर सक्रिय रहती है। जब भी कोई नेहरू परिवार से हटकर राजनीति मे सक्रिय होता है तब यह चौकडी तरह तरह के जाल बुनना शुरू कर देती है । स्वाभाविक है कि नरसिंह राव को भी इसी योजना के अंतर्गत बदनाम किया गया जिसमे कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई और गठबंधन सरकारों की मजबूरी आई । विपक्ष की सरकारों को भी आर्थिक उदारीकरण की गति कम करनी पडी। हालत तो यहॉ तक आई कि मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री होते हुए भी उदारीकरण के शत्रु साम्यवादियों के साथ समझौते करने पडे। राजनैतिक सत्ता के उदारीकरण की तो शुरूआत ही नही हो सकी किन्तु आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण मे भी बाधाएँ पैदा करके उसकी गति को रोका गया। अब साम्यवादियो का पंजा हटा और मनमोहन सरकार उदारीकरण की दिशा मे बढने लगी। मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के साथ साथ राजनैतिक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की दिशा में भी बढना शुरू किया। ग्राम सभाओं को सशक्त किया जाने लगा । उन्हे राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकार भी तेजी से देने शुरू हुए । मनमोहन सिंह की प्रतिष्ठा बढने लगी। कांग्रेस की चौकडी को चिन्ता हुई। वह तो राहुल गांधी के तैयार होते तक के लिये मनमोहन सिंह को खडाउ से आगे नही देखना चाहती थी किन्तु जब पानी सर से उपर जाता दिखा तो चौकडी ने मनमोहन सिंह के विरूद्ध वातावरण बनाना शुरू किया । इस वातावरण निर्माण मे सोनिया कितना शामिल है यह पता नहीं। राहुल गांधी भी बहकावे मे चौकडी के साथ है या सोच समझकर यह भी निश्चित नही किन्तु चौकडी पूरी तरह सक्रिय है यह निश्चित है। विपक्ष मे कोई ऐसा था नही जो इतना समझ पाता । जो साम्यवादी समझने की क्षमता रखते थे वे इस योजना के साथ हो गये। एक समय तो ऐसा लगने लगा कि अव मनमोहन सिंह दो चार दिन के ही मेहमान है किन्तु एकाएक कुछ करिश्मा हुआ और वे बच गये।

जब आर्थिक सत्ता विकेन्द्रित होती है किन्तु तंत्र की सत्ता विकेन्द्रीत नही होती तब उसके कुछ स्वाभाविक दुष्परिणाम भी होते है । उदारीकरण के पूर्व तो सिर्फ राज्य ही धन संग्रह कर सकता था किन्तु जब समाज को आर्थिक आजादी मिली और राजनैतिक गुलामी बनी रही तब पूंजीपतियों ने राज्य शक्ति के साथ भ्रष्ट समझौते करके अपनी आर्थिक शक्ति बढानी शुरू कर दी । बुद्धि और धन को खुला आसमान मिला और खुले आसमान मे उडने की छूट भी मिली। गरीब ग्रामीण श्रमजीवी तो बेचारा इस आसमान मे उडने की छूट के बाद भी कुछ ही दूर तक जा पाया किन्तु बुद्धिजीवी तो टेक्नोलाजी और राज्य शक्ति का सहारा पाकर तेज गति से बढने लगा और यदि बुद्धि के साथ धन भी जुड जावे तो फिर ता उसकी शक्ति असीम हो जाती है । परिणाम हुआ कि आर्थिक असमानता बहुत तेजी से बढी । बहुत थोडे ही समय मे साइकिल मोटरसाईकिल मे और मोटर साईकिल कार मे बदल गई। बुद्धिजीवी पूंजीपति वर्ग यही तक सीमित न रहकर उसने राजनेताओ के साथ षणयंत्र करके ऐसी नीति बनाई कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई । किसान आत्महत्या कने लगे। श्रम बुद्धिजीवियों पूंजीपतियो की मनमानी शर्तो पर श्रम कार्य करने के लिये मजबूर हो गया। ग्रामीण श्रमजीवियो के एक अंश ने तो शहरों मे रोजगार खोजकर किसी तरह जान बचाई किन्तु किसान बेचारा कहॉ जाय। या तो वह श्रमिक बन जाय अथवा घुटघुट कर मर जाय। तंत्र ने तो प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सीमा तक उडने की स्वतंत्रता दे दी। किन्तु उसी तंत्र ने बुद्धिजीवी पूंजीपति को सस्ती कृत्रिम उर्जा का सहारा दे दिया और कृषि उत्पादन वन उत्पादन जैसी वस्तुओ पर भारी करों का पत्थर बांध दिया। बेचारा गरीब ग्रामीण श्रमजीवी पहले से ही बुद्धिजीवी और पूंजीपति से प्रतिस्पर्धा मे बहुत कमजोर था तो उपर से करों के बोझ ने उसकी गति बहुत कम कर दी।

भ्रष्टाचार आर्थिक उदारीकरण का स्वाभाविक परिणाम होता है। राजनैतिक शक्ति यदि केन्द्रित होगी और आर्थिक शक्ति विकेन्द्रित होगी तो इसके अतिरिक्त किसी अन्य परिणाम की आशा करना ही व्यर्थ है । जब आवागमन सस्ता और सुलभ होगा तो ग्रामीण अर्थ व्यवस्था कमजोर तथा शहरी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी ही। आप इसे रोक नहीं सकते। गरीब ग्रामीण श्रमजीवी

किसान के भविष्य की रूपरेंखा भी तो शहरी बुद्धिजीवी पूंजीपति राजनेता ही बैठकर बनाता है। वही हुआ भी । शिक्षा तेजी ते बढी और ज्ञान तेजी से घटा । अच्छे अच्छे घरो के बच्चे ज्ञान और शिक्षा का अंतर नही बता पाते क्योकि ज्ञान का विस्तार तो उसके पारिवारिक सामाजिक जीवन तक ही सीमित है किन्तु शिक्षा का विस्तार उसकी आर्थिक प्रगति मे काम आयगा। हर परिवार सोचता है कि यदि उसके पास पैसा रहा तो वह श्रम तो खरीद कर काम चला ही लेगा। आर्थिक उदारीकरण ने भारत को दो भारतों मे बदल कर रख दिया । एक वह जो उच्च तकनीक सस्ती कृत्रिम उर्जा सस्ता आवागमन अनियंत्रित धन सम्पदा पर सवार होकर हवाई जहाज की रफतार से आगे बढ रहा है तो दूसरा विभिन्न टैक्सो का बोझ लादे धीरे धीरे घिसट रहा है।

दुख की बात है कि आर्थिक उदारीकरण से पूर्व के समाजवादी इस असहाय भारत को राजनैतिक गुलामी से मुक्ति की ओर प्रेरित न करके आर्थिक उदारीकरण के विरूद्ध भडकाने मे संलग्न है। वैसे तो अकेन्द्रीयकरण ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है किन्तु यदि वह वर्तमान मे संभव न हो तो संपूर्ण उदारीकरण तो होना ही चाहिये जिसमे राज्य शक्ति और अर्थशक्ति का अधिकतम विकेन्दोयकरण होना है। सिर्फ अर्थ शक्ति का विकेन्द्रीयकरण पर्याप्त नहीं। उदारीकरण तो आवश्यक है हीं। अब भारत इक्यान्नवे के पूर्व की आर्थिक गुलामी की ओर नही लौट सकता । किन्तु यह भी आवश्यक है कि भारत अब राजनैतिक उदारीकरण की दिशा मे भी तेजी से बढे। जब तक लोक और तंत्र के बीच की बढती दूरी कम नही होती तब तक समस्याए सुलझ ही नही सकती और लोक एंव तंत्र के बीच की दूरी ये लोग कम नही होने देना चाहते । इसके विपरीत ये लोग तो इक्यान्नवे के बाद शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण को भी समाप्त करने के पक्षधर है । इसका अर्थ होगा कि वर्तमान समय मे जो दो भारत सम्पन्न और विपन्न के रूप मे दिख रहे है वे बदलकर सर्वशक्तिमान तंत्र और गुलाम लोक के रूप मे दिखने लगेगे क्योकि वर्तमान मे राज्य मुक्त अर्थ व्यवस्था पर भी बदलकर राज्य का ही एकाधिकार हो जायगा।

मैने आज ही युवा भारत मासिक पत्रिका मे एक समाचार पढा कि उन्तीस मई को हैदराबाद मे सम्मेलन करके एक सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई जो आचार्य नरेन्द्र देव , लोहिया जयप्रकाश के मार्ग पर चलकर एक नया विकल्प खडा करेगी। चूंकि मै प्रारंभ से ही समाजवादी विचारो का रहा इसलिये मै नही समझ सका कि यह पार्टी आचार्य नरेन्द्र देव के समाजवाद पर चलेगी या लोहिया और जयप्रकाश के । गांधी जी संपूर्ण लोक स्वराज्य के पक्षधर थे जिसमे राजनैतिक तथा आर्थिक स्वायतत्ता गांवो को देने की बात थी। जयप्रकाश जी भी करीब बरीब इसी लाइन को समाजवाद कहते थे। लोहिया जी लोकस्वराज्य की जगह चौखम्भा राज्य तथा सप्त क्रान्ति के समन्वय को समाजवाद कहते थे। आचार्य नरेन्द्र देव सत्ता और अर्थ के सरकार के पास केन्द्रित होने को समाजवाद कहते रहे। हमारे भारत मे एक बडी बुराई घर कर गई है कि किसी महापुरूष के मरते ही उसके नाम पर उसकी सोच के ठीक विपरीत एक दुकान खोल दी जाती है जो महापुरूष के नाम और चित्र तक ही सीमित रहती है। गांधी के साथ सर्वोदय ने वही किया जिसने अकेन्द्रीयकरण को पूरी तरह त्याग कर सत्ता और अर्थ के केन्द्रीयकरण की माला जपने लगे। लोहिया जी के साथ भी वही हुआ कि चौखंभा राज्य को लात मारकर आर्थिक उदारीकरण के विरोध तक सीमित हो गये, बेचारे हेडगेवार के साथ भी वही हुआ। हेडगेवार जीवन भर समाज सशक्तिकरण के पक्ष और राजनीति से दूरी बनाने की बात करते रहे किन्तु उनके बाद के संघ ने एक जनसंघ रूपी पुत्र पैदा कर लिया और अब दिन रात भाजपा मोह मे सारा समाज सशक्तिकरण छोड बैठी है । आवश्यकता है कि इन महापुरूषो के नाम पर चल रही दुकानो से सतर्क रहा जाय। हमे यह तय करना होगा कि चाहे किसी महापुरूष ने कुछ कहा हो किन्तु आज की आवश्यकता है संपूर्ण उदारीकरण जिसका अर्थ है राज्य सत्ता आर अर्थ सत्ता का पूरी तरह स्थानीयकरण। हमे बुद्धिजीवी पूंजीपति शहरी गठजोड से मुक्ति तो चाहिये किन्तु वैसी राजनैतिक गुलामी की कीमत पर नही जैसी इक्यान्नवे के पूर्व थी । जो लोग वैसा सपना देख रहे है वे भ्रम मे है, गलत है। मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक उदारीकरण के साथ साथ पिछले एक वर्ष से राजनैतिक उदारीकरण की दिशा पकडी है। अन्ना हजारे जी ने भी एक बहुत अच्छी पहल की है। चौकडी को इस बात से मतलब नही कि उदारीकरण होगा अथवा केन्द्रीयकरण। उसे इस बात से भी मतलब नहीं कि अन्ना सफल होते है या असफल। उसका तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मनमोहन सिंह किसी भी तरह कमजोर हो जिससे नेहरू परिवार के नाम पर राहुल गांधी को बिठा दिया जावे । हमारा कर्तव्य है कि हम चौकडी के इस नापाक इरादे को सफल न होने दे। हम अन्ना जी के आंदोलन को पूरी तरह समर्थन और सहयोग करते रहें। साथ ही हम निरंतर प्रयत्नशील रहें कि हमारी सरकार गरीब ग्रामीण श्रमजीवी किसान के प्रति इतनी संवेदनशील हो कि कोई भी इन्हे बहका फुसलाकर इक्यान्नवे के पूर्व की भयावह स्थिति के पक्ष मे न कर सके । हम उदारीकरण के नाम पर बढती आर्थिक असमानता का भरपूर विरोध भी करेगें और नया मार्ग भी तलाशेगें किन्तु हम यह सारा कार्य पूरी सतर्कता से करेंगे कि कोई अन्य हमारी इस कमजोरी का लाभ न उठा सके।

क्या हम्माम में सब नंगे हैं?

भारत में एक धारणा तेजी से विकसित की जा रही है कि भारत की न्यायिक प्रकिया दाष रहित है और उसकी समीक्षा न्यायपालिका के अतिरिक्त संभव नही हैं। स्वतंत्रता के बाद विधायिका ने भी समाज के समक्ष यही अवधारणा प्रस्तुत की कि समाज न्यायपालिका की समीक्षा न्यायिक सीमाओं से बाहर जाकर नहीं कर सकता। यदि न्यायिक प्रकिया की समीक्षा करनी भी होगी तो वह विधायिका ही कर सकती है और वह भी संविधान संशोधन द्वारा ही। इस तरह विधायिका ने स्वयं को तो न्यायपालिका से उपर मान लिया किन्तु समाज को ऐसी समीक्षा से बाहर कर दिया। विधायिका ने यह स्टैन्ड कर लिया कि वह जन प्रतिनिधि है और उसे संविधान संशोधन तक के असीम अधिकार प्राप्त हैं। न्यायपालिका की सीमाऍ हैं, किन्तु विधायिका की कोई सीमा नहीं। इस तरह विधायिका ने यह धारण फैलाई कि समाज को सिर्फ वोट देने का अधिकार है। उसके बाद उसके सारे अधिकार विधायिका के पास नये चुनाव तक के लिये स्थानान्तरित हो जाते हैं । तथा विधायिका ही संसदीय लोकतंत्र में सर्वोच्च है और वही एक प्रकार से समाज है क्योंकि समाज ही उसे चुनकर वहॉ बिठाता है। यदि दूसरी भाषा में कहें तो संसदीय लोकतंत्र एक सामाजिक तिजोरी है जिसके उपयोग के असीमित अधिकार संसद के पास होते हैं। समाज तो पांच वर्ष में उसकी चाभी का मालिक बदल सकता है। बीच में समाज कुछ नहीं कर सकता चाहे संसद उस तिजोरी को पूरी तरह खाली ही क्यों न कर दे। संविधान निर्माताओं ने समाज के साथ इस सीमा तक विश्वासघात किया कि उन्होंने संविधान में वर्णित मूल अधिकार संशोधन तक के असीमित अधिकार अपने पास ही समेट लिये। विधायिका ने अपने इस अधिकार का इस सीमा तक दुरूपयोग शुरू किया कि उसने संविधान में संशोधन करके एक ऐसा प्रावधान बना दिया कि विधायिका किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा से भी बाहर रख सकती है।

उन्नीस सौ तिहत्तर में केशवानन्द भारती केश में तेरह जजों की सर्वोच्च बेंच ने सिर्फ एक के बहुमत से निर्णय दिया कि संसद को संविधान में संशोधन करने के अधिकार उस सीमा तक ही हैं जहॉ तक उसका मूल ढांचा प्रभावित न हो। न्यायालय ने उसके बाद आज तक मूल ढांचा की कभी व्याख्या नहीं की।

आपातकाल लगने के बाद संसद ने केशवानन्द भारती निर्णय को फिर किनारे करने की कोशिश की। तेरह न्यायधीश बैठे। मुख्य न्यायधीश निर्णय को किनारे करने के पक्ष में थे। अन्य कुछ लोग पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में। मतदान के पूर्व ही मुख्य न्यायधीश ने विचार को समाप्त घोषित कर दिया। इस विचार मंथन के समय सरकार ने तर्क दिया था कि आपातकाल में मूल अधिकार निलम्बित हो जाते हैं तथा सरकार को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताये गोली मार दे। तीस वर्ष बाद न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को किसी भी संविधान संशोधन द्वारा अपने कानून को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखने के असीम अधिकार नहीं हैं।

इस तरह न्यायालय ने विधायिका के कुछ अवांछित पंख कतर कर एक अच्छा काम किया। जनता ने न्यायपालिका को भगवान के समान मानना शुरू किया क्योंकि उसने ही समाज को विधायिका के खूनी पंजे से बचा लिया था। अब न्यायपालिका की बारी आई। न्यायपालिका ने भी स्वयं को समाज से उपर मानना शुरू कर दिया। बदनाम विधायिका तो न्यायपालिका पर कोई अंकुश लगा ही नहीं सकती थी और समाज को किसी पर कोई अंकुश लगाने का कोई अधिकार था ही नहीं। समाज पांच वर्ष में एकबार सिर्फ नयी संसद को ही बना सकता है और संसद इतनी बदनाम हो चुकी है कि उसे न्यायपालिका के सीमा अतिकमण के विरूद्ध कुछ बोलने तक की हिम्मत नहीं।

इस समय न्यायपालिका को समाज के बीच सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। विचारणीय प्रश्न यह नहीं है कि उसके जज कैसे हैं? विचारणीय प्रश्न यह है कि यह प्रकिया कितनी ठीक है। संविधान संशोधन के असीम अधिकार संसद को दिये जाने के दुष्परिणाम पचहत्तर के आपात्काल के रूप में सामने आया और तब पता चला कि ऐसे अधिकारों का किस सीमा तक दुरूपयोग संभव है। अतः न्यायिक प्रकिया को विधायिका और कार्यपालिका के उपर असीम अधिकार देने की प्रकिया की समीक्षा आवश्यक है। मैं दो तीन मामलों की चर्चा करना उचित समझता हूँ जो न्यायिक प्रकिया की समीक्षा आवश्यक मानते हैं।

केशवानन्द भारती प्रकरण में तेरह में से सात जजों ने यह माना कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन के असीम अधिकार प्राप्त नहीं हैं। दूसरी ओर छः न्यायधीशों ने ऐसे अधिकार को स्वीकार किया। इसका अर्थ यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के तेरह में से छः न्यायाधीश संसद सर्वोच्च के पक्ष में थे। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि उस समय सिर्फ एक जज इधर से उधर हो जाता तो भारत के संसदीय लोकतंत्र का सम्पूर्ण ढांचा इधर से उधर हो गया होता। तब संसद आपात्काल को भी पूरी तरह आदर्श घोषित कर देती। तब सरकार किसी भी सीमा तक बिना कारण बताये गोली मार सकती थी। क्या हम ऐसी न्यायिक प्रकिया को आदर्श कहें जिसमें एक सौ इक्कीस करोड़ लोगों का भाग्य किसी एक व्यक्ति के हां और ना पर आकर टिक जावे और ऐसे निर्णय की कहीं अपील का भी कोई प्रावधान न हो। यह न तो कोई साधारण सा कानूनी मामला था न ही सिर्फ साधारण संवैधानिक मामला। यह तो पूरा का पूरा सम्पूर्ण समाज और राज्य के आपसी सम्बन्धों का मामला था । आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं तो हमें अन्तिम निर्णय मानना ही होगा। मैं भी समझता हूँ कि यदि इसके उपर भी कोई कोर्ट बने तो वहॉ भी ऐसी स्थिति आ सकती है। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या ऐसी समस्या का समाधान नहीं खोजा जाना चाहिये। आदर्श स्थिति तो यह होती कि भारतीय संविधान में ऐसी स्थिति की कल्पना करके उसकी व्यवस्था होती और यदि अब तक नहीं है तो अब ऐसी व्यवस्था पर सोचा जाना चाहिये। न्यायपालिका सर्वोच्च है यह बात जबरदस्ती समाज के बीच षड़यंत्र पूर्वक फैलाई जा रही है। न्यायपालिका ने केशवानन्द भारती प्रकरण में निर्णय देकर निरंकुश विधायिका से समाज की रक्षा की है यह बात सच है किन्तु हम दुबारा वैसी ही भूल नहीं कर सकते क्योंकि हमारी न्यायिक प्रकिया भी आदर्श न होकर विकल्प तलाश रही है। अब तक हमारे समक्ष उतना खतरा नहीं था कि कभी न्यायपालिका अपने अधिकारों का दुरूपयोग भी कर सकती है किन्तु अब कुछ कुछ इसलिये दिखने लगा है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के भी अधिकार समेटने में लगी है और विधायिका के भी। हम भुगत चुके हैं कि हमारी राजनैतिक शक्ति के पास ऐसे अधिकार इकट्ठे होने लगे तब तीस चालीस वर्ष बाद हमें खतरा आभास हुआ। अब यदि न्यायपालिका इस तरह करेगी तब भविष्य की चिन्ता तो स्वाभाविक ही है।

आखिर न्यायपालिका में भी मनुश्य ही हैं। वे भी दया धर्म न्याय लोभ लालच से प्रभावित हो सकते हैं। हमने एक केश को समझने का प्रयास किया। एक व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप में जेल में बन्द किया गया। उस व्यक्ति ने मुकदमा चलते तक जमानत के लिये दरखास्त दी। दरखास्त सर्वोच्च न्यायालय तक ने यह कह कर कई बार खारिज की कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए केश चलते तक भी इसे बाहर रखना खतरनाक होगा। दो वर्ष बाद उसे किसी तरह जमानत मिली। केश का फैसला हुआ। आरोप प्रमाणित हुए। व्यक्ति को आजीवन कारावास हुआ। दुनिया भर में हल्ला हुआ। मीडिया ने भी प्रश्न उठाये। राजनीति भी सकिय हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने उसी दोष सिद्ध व्यक्ति को इस टिप्पणी के साथ जमानत दे दी कि ये आरोप किसी भी रूप में खतरनाक नहीं हैं। विचारणीय प्रश्न जमानत का न होकर उस टिप्पणी का है। न्यायपालिका एक संवैधानिक इकाई है, कोई व्यक्ति नहीं। किसी व्यक्ति को आरोप परीक्षण के दौरान इतना गंभीर अपराधी माना जाय कि उसका बाहर घूमना भी खतरनाक है और उसी व्यक्ति को वही न्यायालय वही आरोप सिद्ध हो जाने के बाद ऐसा सामान्य अपराध मान ले जैसे कि यह कोई खास अपराध ही नहीं है तो प्रश्न उठता है कि दोना में अन्तर क्या हुआ? व्यक्ति वही। अपराध वही। न्यायालय वही। परीक्षण के दौरान अपराध बहुत खतरनाक और सिद्ध तथा सजा होने के बाद अपराध बहुत मामूली। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बात बाद में मीडिया और विदेशी चर्चाओं के बाद न्यायपालिका के समझ में आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यायपालिका प्रचार से प्रभावित हो गई? जिस व्यक्ति को दो वर्ष तक जिस आरोप में जेल में रहने के कारण समाज ने जो धारणा बना ली उस समाज को अब उस व्यक्ति के आरोप प्रमाणित होने के बाद भी उसी न्यायालय की टिप्पणी ने भ्रम में डाल दिया कि एक ही न्यायालय की दो भूमिकाओं के बीच न्याय क्या है?

हम देख रहे हैं कि न्यायपालिका आये दिन सरकार से पूछती रहती है कि इस समस्या के समाधान के लिये आपकी योजना क्या है? इसके साथ ही न्यायपालिका सरकार से यह भी पूछती है कि आपके समाधान की समय सीमा क्या है और कभी कभो तो न्यायपालिका ऐसे प्रयत्नों को अपर्याप्त मानकर अपनी एस आई टी अर्थात मोनिटरिंग कमेटी भी बना देती है। मैं आज तक नहीं समझ सका कि हमारी न्यायपालिका वर्तमान सरकार से नक्सलवाद के समाधान के लिये ऐसे प्रश्न क्यों नहीं करती? भारत की जनता महसूस करती है कि वर्तमान सरकार या सरकारें नक्सलवाद का समाधान नहीं कर पा रहीं और जो काम सरकार नहीं कर पा रही वह काम न्यायालय के हस्तक्षेप से तत्काल संभव हो जा रहा है। या तो न्यायपालिका नक्सलवाद को गंभीर खतरा नही समझ रही अथवा वह इसे इतना गंभीर मानती है कि हाथ डालना ही नहीं चाहती। कारण क्या है वह वे जाने। मुझे ऐसा लगता है कि यदि न्यायपालिका इस समस्या के समाधान का जिम्मा ले ले तो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था पर आये एक खतरे से मुक्ति मिल जायगी। मुझे विश्वास है कि न्यायालय ऐसी पहल करेगा।

इस समीक्षा के बाद भी यह प्रश्न नहीं सुलझा कि इसका समाधान क्या है? विधायिका के खतरे से न्यायपालिका ने बचाया और न्यायपालिका से संभावित खतरे से बचने के लिये पुनः विधायिका को सशक्त करना तो और भी ज्यादा घातक होगा। निरंकुश विधायिका निरंकुश न्यायपालिका की अपेक्षा कई गुना ज्यादा खतरनाक सिद्ध होगी। न तो हम न्यायपालिका की वर्तमान स्थिति को आदर्ष कहने की स्थिति में है न ही कुछ वर्ष पूर्व की विधायी निरंकुशता का समर्थन कर सकते हैं। हमें इन सबसे अलग हटकर कोई मार्ग तलाशना होगा। न विधायिका की नीयत में दोष है न न्यायपालिका के। दोष तो है सिर्फ अधिकारों के केन्द्रीयकरण में। भारतीय संविधान को गाड़ी में लगे गर्वनर के समान होना चाहिये था जिसकी गाड़ी के किसी संचालन में किसी प्रकार की भूमिका तो न हो किन्तु वह गाड़ी को एक सीमा से आगे जाते ही नियंत्रित कर ले। भारतीय संविधान रूपी ऐसा गर्वनर तो है किन्तु गाड़ी निर्माता ने यदि यह भूल कर दी कि गाड़ी का ड्राइवर या यात्री, गवर्नर में तय चाल को कम ज्यादा कर सकता है तो गर्वनर का उपयोग अप्रभावी हो जायगा। हमारे संविधान निर्माताओं से उस समय चाहे जो भूल हुई हो किन्तु अब तो वह भूल सुधरनी ही चाहिये। सर्वोच्च विधायिका है या न्यायपालिका यह प्रतिस्पर्धा तब तक तो चल सकती है जब तक सर्वोच्च समाज न हो किन्तु यदि एक बार समाज ने यह घोषित कर दिया कि हम सर्वोच्च हैं तो ये विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के सारे झगड़े अपने आप खत्म हो जायेंगे। भारतीय संविधान रुपी गर्वनर भी हमारे पास है जो इन तीनों की सीमा से आगे जाते ही उन्हें नियंत्रित कर सकता है किन्तु हमसे यह भूल हुई कि उस संविधान से छेड़छाड़ के भी व्यापक अधिकार हम उन्हें ही दे बैठे।

आज अन्ना जी की टीम कुछ सार्थक प्रयास कर रही है। लोकपाल आंदोलन कोई व्यापक सुधार नहीं कर पायेगा। यह तो इस संघर्ष का पहला चरण है। चाहे अन्ना जी जीतें या सरकार किन्तु इसका दूसरा चरण राइट टू रिकाल से शुरू होना चाहिये। उसमें चाहे हम जीतें या हारें किन्तु इसका तीसरा चरण ग्राम सभाओं को विधायी अधिकार से शुरू होना चाहिये। और तब उसके बाद इस लडाई का चौथा चरण संविधान संशोधन अधिकार का होगा और यह चरण अन्तिम तथा निर्णायक होगा। संविधान हम भारत के लोगों का है जिसे हमने तंत्र को सौपा है। वह भी कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका के समन्वय की शर्तों पर। यदि ये आपस में एक मत न हों अथवा ये हमारे ही विरूद्ध एक मत होने का प्रयास करें तो हमें यह आवाज उठाने का अधिकार है कि हम संविधान संशोधन का अधिकार एक नई व्यवस्था को देना चाहते हैं। एक ऐसी समिति बने जो कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका तथा नागरिक समिति के लोग बनावें और वह समिति ऐसा प्रारुप बनावे जो संविधान संशोधन प्रकिया के लिये उपयुक्त हो। इस संविधान संशोधन समिति में तंत्र से जुड़े लोग न हों क्योंकि तंत्र तो संविधान संशोधन का प्रस्ताव देगा ही। वही प्रस्ताव करे, वही समीक्षा करे और वही पास करे यह गलत है। तंत्र से बाहर की समिति उक्त प्रस्ताव को स्वीकार अस्वीकार या संशोधन का सुझाव दे सकती है। तंत्र तथा लोक समिति मिलकर जो तय करेंगे वही संशोधन संविधान में होगा, अन्यथा नहीं। हमें अन्त में तो यहीं आकर लडाई समाप्त करनी होगी। आज भले ही हम लाकपाल से शुद्ध करें यह अलग बात है।

हमने संविधान रूपी हम्माम में तीन शक्तियों को छोड़ दिया है। तीनों एक दूसरे को नंगा सिद्ध करने के प्रयास में हमें ही परेशान कर रही है। हमें न तो इन तीनों के विवाद में पड़ना चाहिये न ही किसी भी एक से कोई ज्यादा उम्मीद करनी चाहिये। हम तो उस तालाब का एक बार पानी निकाल दें तो सारी समस्याएँ सदा के लिये सुलझ जायेंगी। क्योंकि तब तीनों को पता चल जायगा कि हम्माम में सब नंगे हैं। कपड़े वाला तो बाहर बैठा है जिसने हम्माम का पानी बाहर निकाल कर हमे यर्थाथ बता दिया है।

युवा संवाद जुलाई ग्यारह का सम्पादकीय

जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध

निरंकुश राज्य पर अंकुश लगाने और व्यवस्था में अधिकतम पारदर्शिता लाने के लिए एक तरह से महाभारत की तैयारी शुरू हो गई हैं। इसे लोकपाल क्रांति भी कह सकते हैं या पारदर्शिता क्रांति भी। एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार है जिसने आंदोलन ,अनशन और नागरिक समाज का किसी तरह का दबाव न मानने और उससे सख्ती से निपटने का संकल्प ले रखा है तों दूसरी तरफ एक बूढ़े की नैतिक ताकत के सहारे खड़ा नागरिक समाज बिना कुछ हासिल किए पीछे हटता नहीं दिखता । अन्ना हजारे और उनके साथियों ने चेतावनी दे रखी है कि अगर 15 अगस्त तक जन लोकपाल नहीं बन पाया तो वे 16 अगस्त से फिर अनशन पर जाएंगे । कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में अध्यक्ष सोनिया गांधी ,प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आर महासचिव राहुल गांधी ने ऐसे किसी आंदोलन के खिलाफ सख्त कदम उठाने का संकल्प लिया है और जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन असली इरादे तो वी पी सिंह और अर्जुन सिंह बनते –बनते अमर सिंह बनने का लोभ पाल लेने वाले दिग्विजय सिंह के बयानो में दिखाई पड़ता है। दिग्विजय सिंह भले बाद में अपने बयान से पलट गए हों लेकिन उनके इस बयान का खास मतलब है कि अगर इस बार अन्ना ने अनशन किया तो उनकी भी स्थिति वही की जाएगी जो रामदेव की हुई है।बाद मे कांग्रेस कार्य समिति ने भी लगभग वही रूख अपनाया है। इसी के साथ दिग्विजय सिंह बार–बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का भी आह्वाहन भी कर रहें हैं । ध्यान देने की बात है। कि उनके बयानों में कहीं भी यह बात नहीं कही जाती कि इस देश की गरीबी को मिटाना है या समानता लानी है । यह सब बातें वे सामाजिक न्याय के वोट बैंक वाले एजेंडे के तहत भले करें लेकिन उसे वे उस व्यापक विमर्श में नहीं लाते जिनसे नीतियो में बदलाव हो। वे मानते हैं कि एक तरफ युवराज को सत्ता देने की तैयारी चल रही है। तो दूसरी तरफ विध्न डालने वाला नागरिक समाज आंदोलन करने पर आमादा है। ये दोनो पक्ष अपने अपने लिए समर्थन जुटाने में लगे है। कांग्रेस जुलाई के पहले हप्ते में होने वाली सर्वदलीय बैठक में अपने मसौदे को मंजूरी दिलाना चाहती है तो अन्ना हजारे और उनके साथी अपना शुद्धतावाद छोड़कर राजनीतिक दलों से समर्थन जुटा रहे है। उन्होने सबसे पहले अपना पक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के सामने रखा है। वे अन्य दलों के पास भी जाएंगे । यह काम सरकार और कांग्रेस पार्टी भी करेगी। ऐसे में यह सवाल बहुत बड़ा है कि क्या किया जाए? यह धर्मसंकट उनके सामने बहुत बड़ा है जो न तो कांग्रेसी हैं न ही भाजपाई । न ही धर्मनिरपेक्ष बनने के लिए कांग्रेस के प्रमाणपत्र की आवश्यकता है न ही ईमानदार दिखने के लिए भाजपा के सनद की।तेजी से होते इस राजनीतिक ध्रुवीकरण में वे लड़ाई को किसी और दिशा में मोड़ नहीं सकते और अपना इस्तेमाल होने देना नहीं चाहते। क्या वे भीष्म और कृपाचार्य की तरह उनके साथ हो लें जिनका उन्होने अन्न खाया है? या वे विदुर की तरह उपदेश देकर खामोश हो जाएं और युद्ध के लिए लाचारी जता दें ? ऐसा व्यवहार वामपंथी और समाजवादी बुद्धिजीवी कर रहे है। या वे कृष्ण की तरह इस युद्ध में अपनी सेना दुर्योधन के साथ भेज दें और स्वयं अर्जुन के साथ हो लें और हथियार न उठाने की कसम खाते हुए समय–समय पर हथियार उठाते रहें ? एक विकल्प बरबरीक बनने का भी है जो युद्ध में कमजोर पड़ते किसी भी पक्ष की तरफ से युद्ध करने को तैयार रहता था। हालांकि कृष्ण ने उसे युद्ध नहीं लड़ने दिया और उसके पहले ही समाप्त कर दिया । हो सकता है इस बरबरीक को मरने के बजाय जिंदा

रखा जाए और उसे युद्ध में भ्रम पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए । सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में सकिय नागरिक समाज ऐसा ही कर रहा हैं । वह सरकारी नागरिक समाज बनकर एक तरफ विधेयक तैयार करवाता है तो दूसरी तरफ जब सरकार और कांग्रेस के प्रतिनिधि यह धमकी देते है कि यह हक नागरिक समाज का नहीं है तो वे चुप हो जाते हैं।

इसके अलावा एक तरीका बलराम का था । वे महाभारत छिड़ने के समय चारों धाम यात्रा पर निकल गए थे । आखिर में लौटे तो जब सारी बुराइयों की जड़ में बैठा उनका शिष्य दुर्योधन अनीति से मारा जा रहा था तो गुस्से से उबल पड़े। इनमें से कोई न कोई भूमिका हम सभी को पुकार रहो है। लेकिन एक बात स्पष्ट लग रही है कि चाहे इसे पारदर्शिता क्रांति कहें या लोकपाल क्रांति पर इसके प्रति आम जनता में एक तरह की ललक पैदा हुई है। यह ललक इसलिए पैदा हुई है कि उदारीकरण ने पिछले बीस सालों में बेहद भ्रष्ट शासक और क्रूर व्यवस्था को जन्म दिया है। भ्रष्ट वे भी है जो बेहद शालीन दिखते है और वे भी जो अशिष्ट और और अभद्र । आखिर इस बात से कौन इंकार कर सकता है। आज उत्तरप्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसकी जड़ में भ्रष्टाचार ही है। काढ़ा तैयार किया है। उससे समाज का स्वास्थ्य ठीक होने के बजाय लगातार बिगड़ता जा रहा है। उसने समाज में एक विकृत बदलाव किया और राज्य के तंत्र को या तो अपने चरणों में या शैया पर लिटा दिया है। यह भ्रष्ट व्यवस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के भ्रष्ट अध्यक्ष की नोटिसों से नहीं सुधरने वाली है न ही सुप्रीम कोर्ट के पार्टटाइम निगरानी या कार्यकमो से । न ही इसके खिलाफ होने वाली लोकपाल क्रांति को सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की दीवारों से रोका जा सकेगाा।लड़ाई शुरू हो चुकी है और उसका एक चरण पूरा भी हो चुका है। अब वह उस कठिन दौर में प्रवेश करने जा रही हैजहां सत्ता पर सीधे आंच आने वाली है।इसलिए अपनी अपनी भूमिका की तैयारी करनी होगी । वरना दिनकर के शब्दो में जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध।

पत्रोत्तर

1. आचार्य पंकज, राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यवस्था परिवर्तन मंच, रिषिकेष हरिद्वार

प्रश्न–राजाओं के राज्यों में जो ऐतिहासिक पाठ हमने सीखे, वे अब काम के नहीं रहे। जब तक इन पाठों को हम न भूलेंगे, लोक–राज मजबूत नहीं होगा। आज तक तो सत्ता–परिवर्तन ही होता रहा, पर अब जीवन–परिवर्तन के दिन आये हैं और इस जीवन–परिवर्तन की बुनियाद में बड़ा ही कांतिकारी मानस–परिवर्तन है। यह मानस–परिवर्तन भारत के कोने–कोने तक, गॉव–गॉव तक अभी पहुंचा नहीं है। इसीलिये समाज–परिवर्तन करने में कठिनाइयॉ महसूस होती है और लोक–राज स्थापित होने में देर लग रही है। पुरानी–राजनीति, पुराना इतिहास और पुराने धर्मशास्त्र अब कालग्रस्त हो गये हैं। उनका स्थान अब लोक–जीवन में नहीं, किन्तु अजायबघरों में है। हर एक धर्म की अपनी शास्त्र–ग्रन्थों की पूंजी होती है। इन धर्म–ग्रन्थों के बल पर ही धर्मों का राज आज तक चला। अब ऐसे दिन आये हैं कि धर्म–ग्रन्थों का राज भी टूट रहा है। शास्त्रों द्वारा किया हुआ जीवन–संगठन हजारों बरस चलकर अब खोखला हो रहा है। गान्धी, बिनोबा, काका कालेलकर, जयप्रकाश और डॉ0 लोहिया आदि ने इसी भाव–भूमि को अपने–अपने चिन्तन में समाविष्ट किया है। ज्ञान–यज्ञ के माध्यम से आप भी संभवतः वही कर रहे हैं। अन्तर यह है कि आप डॉ0 लोहिया तथा जयप्रकाश की तरह कियात्मक भी हैं। ज्ञानतत्व में इस सन्दर्भ में आपका विचार पढ़ने को मिलेगा तो अवश्य हीं मुझे खुशी होगी।

उत्तर–मैं आपकी भावना से पूरी तरह सहमत हूॅ यद्यपि यह कथन कुछ एक तरफ झुक गया है। जो कुछ प्राचीन है वह पूरी तरह गलत है ऐसा मानना ठीक नहीं और जो कुछ पुराना है वह पूरी तरह आदर्श है ऐसा मानना भी ठीक नहीं। पुराने और नये की समीक्षा करके निष्कर्ष निकालना ही उचित होता है। वर्तमान व्यवस्था पुराना सही और पुराना गलत कहने वाले दो अतिवादी समूहों के बीच फंस कर किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई है। ये दोनों समूह न मन्थन करना चाहते हैं न सत्य स्वीकारना चाहते हैं। ये समूह व्यावसायिक पक्षकार बन गये हैं जो येन केन प्रकारेण दिन रात अपने पक्ष का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। ये दोनों ही समूह सामान्य लोगों को भी किसी न किसी गुट में संगठित करते रहते हैं जिस कारण तटस्थ लोगों की संख्या घटती जा रही है और इन गुटों की संख्या बढ़ते जा रही है। इन दोनों ही गुटों की ताकत इस तरह बढ़ रही है कि ये दोनों गुट आपस में हिंसक स्वरूप भी ग्रहण कर लेते हैं। इन दोनों ही गुटों ने किसी न किसी रूप में राजनैतिक सत्ता में भी अपनी घुस पैठ कर ली है। यह स्थिति हम सबके लिये बहुत खतरनाक है।

हम आप जैसे कुछ लोग समाज के दोनों गुटों से दूर स्वयं निष्कर्ष निकालने वाले बचे खुचे लोगों को मजबूत करने का काम कर रहे है। आप जानते हैं कि दोनों ही गुटों के लोग हमारे विरूद्ध दुष्प्रचार में संलग्न रहते हैं। हम जब कहते हैं कि मृत महापुरूषों के विचार बिना स्वयं समीक्षा किये यथावत् स्वीकार करना घातक है तो पुरातन पंथियों को कष्ट होता है। वे अपने–अपने घेरे को हमसे दूर रहने की सलाह देना शुरू कर देते हैं। किन्तु जब हम कहते हैं कि प्रेम विवाह को प्रोत्साहन देना परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था को किनारे करके व्यक्ति परिवार और समाज के संतुलन को क्षति पहुॅचाती है तब नयी समाज व्यवस्था के ठेकेदार हमारे खिलाफ उछलना शुरू कर देते हैं। जब हम कहते हैं कि बार–बार मृत महापुरूषों के आचरण अथवा उन ग्रन्थों के आधार पर अपनी बात पुष्ट करने की अपेक्षा कुछ अपनी स्वयं की बात भी प्रस्तुत करने की आदत डालनी चाहिये तो पुरातन पंथी नाराज हो जाते हैं। दूसरी ओर जब हम कहते हैं कि बार–बार संविधान की धाराओं को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करना अच्छी आदत नही तो आधुनिक लोगों को बुरा लगता है। इसी तरह जब हम कहते हैं कि धर्म से समाज उपर है तो पुरातन पंथियों को कष्ट होता है और जब हम कहते हैं कि राज्य और राष्ट से भी समाज उपर है तब आधुनिक लोगों को कष्ट होता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो दोनों ही गुटों को कष्ट पहुॅचाती हैं।

हम सबकी स्थिति यह है कि इन दोनों ही गुटों के विरोध से हमें आभास होता है कि हम निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। ये दोनों ही गुट हमारे किसी तर्क का उत्तर न देकर व्यक्तिगत आलोचना शुरू कर देते हैं जो उनकी कमजोरी प्रकट करता है। हम न तो कोई संगठन बना रहे हैं न ही किसी विशेष किया में संलग्न हैं। आपने मेरे प्रयत्नों की तुलना गांधी लोहिया जयप्रकाश से की जो पूरी तरह गलत है। गांधी लोहिया जय प्रकाश ने जो किया वह प्रत्यक्ष दिखता है। इन तीनों महापुरूषों ने समाज को एक दिशा दी। मैं तो वैसा कुछ न कर पा रहा हूॅ न ही उतनी क्षमता और योग्यता है। मैं तो मात्र इतना ही समझा पा रहा हूॅ कि स्वयं विचार मंथन की शक्ति को सशक्त करो, किसी के पीछे आंख मूंदकर मत चलो, मेरे साथ भी नहीं, अपनी स्वतंत्रता को कायम रखो, किसी भी घेरे में गुलाम सरीखे रहना छोड़ो। मैं तो यहॉ तक कहता हूॅ कि मेरे कथन पर भी मंथन करो और जो ठीक लगे वह मानो और जो गलत लगे उसका विराध करो। यदि कोई व्यक्ति मेरा विरोध करता है

तब मुझे बुरा लगता है और मैं समझता हूँ कि यह व्यक्ति किसी न किसी गिरोह से अवश्य जुड़ा है। किन्तु यदि कोई व्यक्ति मेरे विचारों का विरोध करता है तब मुझे खुशी होती है और मैं मानता हूँ कि यह व्यक्ति सत्यान्वेषी है, संतुलित है। मैं जैसा भी हूँ या मेरे जो भी विचार हैं वे सब आप जैसे विद्वानों के माध्यम से ही एकत्रित हुए हैं। मेरी जो भी सकियता दिखती है उसमें भी नाम भले ही मेरा दिखता हो किन्तु सच्चाई यह है कि मैं तो ज्ञान तत्व में लिखने के अतिरिक्त कुछ करता ही नहीं। जो भी होता है वह आप सब करते हैं और नाम मेरा ले लेते हैं। आगामी नवंबर माह की आठ तारीख से चालीस दिनों तक उत्तर भारत के पचहत्तर स्थानों पर ज्ञान यज्ञ परिवार, व्यवस्था परिवर्तन मंच, लोक स्वराज्य संघ, ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान, व्यवस्था परिवर्तन अभियान, लोक स्वराज्य मंच, लोक संविधान सभा आदि मिलकर कार्यकम आयोजित करेंगे और जिसमें आप विद्वानों के साथ मैं भी रहूँगा। अन्य विवरण बाद में जायगा।

2 श्री सत्यमेव गुप्त रूदौली बाराबंकी उत्तरप्रदेश

प्रश्न– पॉच हजार वर्ष बीत गए हम निरंतर पतन मार्गी होते गए। धार्मिक सामाजिक राजनीतिक चेतना के अभाव में हम में सामूहिक राष्टीयता घटती गयी। मुगलों के बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया। भारत के इस आत्महत्ता युग में एकाएक गुजरात में महर्षि दयानंद का प्रकट हुआ । ऋषि ने भारत की प्रत्येक रूग्ण नाड़ी का वैध की भांति निरीक्षण किया तथा उपचार स्वरूप उन्होने आर्यसमाज की स्थापना की। अर्थात अनेक दयानंद प्रांत प्रांत में आर्य स्वयं सेवी संगठन । भारत मे विदेशी शासन ने भी उसे समझा और बड़ी युक्ति से स्वामी जी के रसोइये के द्वारा स्वामी जी की जीवन लीला समाप्त करवा दी । परंतु आर्यसमाज ने तो स्वयं को ही स्वामी जी के रूप में पुनर्जीवित कर लिया। आर्य समाज के स्वयं सेवको ने ही स्वाधीनता संग्राम का सफल आंदोलन चलाया तथा आर्य समाजी स्वयं सेवक एक एक करके राष्ट्र की बलि वेदी पर न्योछावर होते गये । इस स्वतंत्रता समर में लगभग सभी आर्य सिपाही शहीद हो चुके थे तो नए विचारो वाले पथ प्रदर्शक भारत में उत्पन्न हा गए और उतावले पन में भारत की हत्या के षड्यत्र में सहभागी बने परिणाम स्वरूप पाकिस्तान बना । विदेशी संस्कृति और सभ्यता के पोषक भारत के कर्ण धार बन बैठे। भारत में नेहरू तथा पाकिस्तान में इस्लाम धर्म का राज्य स्थापित हुआ । कहते है कि जवाहर लाल नेहरू के पिता श्री मोती लाल नेहरू की मुस्लिम उपपत्नी थी –कुछ लेाग मि0 जिना को भी जवाहर लाल का भाई कहते है। मेरे पास ऐसा कोई प्रणाम नही हैं जिससे इस वंश की वंशावली पर प्रमाणित सामग्री उपलब्ध करवा सकूं। नेहरू जी को आारंभ में भारतीय सभ्यता संस्कृति से विशेष लगाव नही था। उन्होंने भारत की बहुत सारी भूमि वंजर कहकर चीन को दे डाली । उस समय वे भारत के सर्वाधिक प्रिय राज कूमार एवं नृपति थे उन्होने जिन्ना को पाकिस्तान दिया उन्होने अपने मुस्लिम भाई शेख को कश्मीर का राज्य प्रदान किया । उस समय कश्मीर में हिन्दू राज्य था।

आर0एस0एस0 नाम की एक गैर राजनीतिक संस्था थी जिसकी शाखाएं लगभग सारे भारत में थी। हिन्दू विचार धारा की इस संस्था का मुख्य कार्य बिखरे हुये विभिन्न हिन्दू समाज को संगम के रूप में शक्तिशाली बनाना था। इसके स्वयं सेवको ने अपने कौशल से भारत की सन्य सहायता पहुँचने तक कश्मीर को पाकिस्तान के जबड़ो में जाने से बचाये रखा । यह रहस्य ही है कि जाति पांति न मानने वाले नेहरू परिवार के किसी पुत्र पुत्री का वैवाहिक सबंध किसी मुस्लिम परिवार से नहीं जुड़ा जब कि इनके परिवार की एक महिला का संबंध एक राजनीतिक मौलाना से था। नेहरू जी का लेडी माउंट बेटन का इश्क तो सर्वविदित ही है। पाकिस्तान इस्लामी राज्य बना तो भारत के हिन्दुओ में भी भारत में हिन्दू राज्य स्थापना की भावना प्रबल हो गई जिस का भारत में ही विरोध हुआ। कांग्रेसी शासन ने तो हिन्दू विचार धारा के वध का निर्णय ही कर डाला । नेहरू शासन ने कश्मीर में भारतीयो के प्रवेश पर रोक लगा दी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने घोषणा कर दी कि भारत मेरा देश है मेरे देश का प्रत्येक प्रांत भी मेरा है वहॉ जाने से मुझे कोई नही रोक सकता । उन्होने अपना वचन पूरा किया और नेहरू ने भी । मुखर्जी कश्मीर गए और उनकी हत्या करवा दी गई। नेहरू सरकार का कुछ नही बिगड़ा । तत्कालीन पत्र पत्रिकाएं इस कृत्य की साक्षी है। तब से अब तक ऐंसी हत्याओ का क्रम जारी है।

जवाहर लाल नेहरू विदेशी संस्कृति के पुजारी राजनोति के कुशल खिलाड़ी थे। ये राजनीति में धर्म के विराधी थे नास्तिक थे। हजरत मुहम्मद के प्रशंसक थे भारतीयता के प्रबल विराधी थे ।जिहालती तक कह देते थे । कहते है कि जीवन की अंतिम अवस्था में उनके भीतर भी भारतीयता के जीवाणु पनपने लगे थे।

चीन युद्ध क पश्चात नेहरू जी अस्वस्थ रहने लगे थें। राज नीति में उतरने से पूर्व वानर सेना की संचालिका मेरे नगर रूदौली में आई। कोई भीड़भाड़ नही थी मात्र इंदिरा को ।

किदवई साहब जिन्होने साठ रूपये तोला सोना तथा एक रू में नौ सेर चना बिकवाया था उन दिनो किसी कारण वश अदृष्य चल रहे थे । एकाएक रूदौली में वे प्रकट हो गए । इंदिरा जी के मंच पर भी आये बैठे किंतु बोले कुछ नहीं । इंदिरा जी बोलने के लिए खड़ी हुई बोली पिता का संदेश और आर्शीवाद ले कर आप के बीच आई हूँ। कहते कहते उन्होने विस्फोट किया कि मैं एक हिन्दू नारी हूँ । निश्चिंत निर्भीक हेाकर नेहरू की बेटी बोल रही थी। बहुत फुसफुसाहट हुई। किदवई साहब बिना किसी प्रतिकिया के मंच से उतर कर चले गए । दूसरे दिन के दैनिक स्वतंत्र भारत की यह मुख्य खबर बनी ।नेहरू जी के अवसान पश्चात् शास्त्री जी की हत्या के बाद इंदिरा को कुर्सी मिली। चारो और राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी और वह नन्ही अकेली इंदिरा। लोग खेलने खिलाने के मूड में थे कि दृष्य ही बदल गया –सब कठपुतली की भांति नाचने लगे। नचाने वाली इंदिरा कांग्रेस में दो फाड़ । मंजे हुंए चतुर खिलाडी एक ओर तथा छुट भइये और धूर्त इंदिरा के साथ। चुनाव मे इंदिरा विजयी। लेाग विस्मित।. न्यायालय से इंदिरा पार्टी शासन के अयोग्य घोषित । किंतु उन्ही चाटुकार लोगो को साथ ले कर कर दी इंदिरा ने आपात काल की घोषणा। भारत ही नही पूरा विश्व हक्का बक्का । साथी चाटुकार धूर्तो ने खूब दांव चले। बदनामी का ठीकरा इंदिरा के उपर। भारत अपलक देख रहा था –भारत की जनता भी अनुभव कर रही थी एकाएक पूरे देश में शांति छा गई चोरी डकैती हत्या का पारा शून्य पर। सरकारी अधिकारी व्यापारी सभी ईमानदार हो गए। बडे बडे बाहुबली भेड़िए अपनी अपनी मांदो में छिप गए । इंदिरा का फरमान सब का हकसमान न हिन्दू न मुसलमान एक समान कानून सब के लिए विशेषाधिकार किसी को नही परिवार नियोजन सब पर समान हस्तक्षेप कर रहा था ।

मैं भी भ्रमित हो गया इदिरा के विरोध में बड़ी ही कट, कविता लिख दी। आपात काल समाप्त जनता में आजादी का उल्लास इन्द्रासन हिल गया । विदूषक राज नारायण ने मजाक मजाक में चुनाव जीत लिया । मुसलमानो के लिये परिवार नियोजन की अनिवार्यता समाप्त । थोड़े दिन जनता राज । सारे देश का शांत वातावरण छिन्न भिन्न। नेता मस्त जनता त्रस्त। फिर चुनाव जनता ने प्रियदर्शिनी को शीश पर उठा लिया। अनुशासन पर्व के बिना ही पहले से भी अधिक शक्ति अर्जित कर ली इंदिरा ने बिना किसी दबाव के ।

मुसलमानो मे बर्थ कन्ट्रोल पर सब को समान रुप से लागू करने पर बहुत गुस्सा था–संजय गांधी से तो वे बहत नाराज थे । गुप्त षड्यंत्र द्वारा संजय गांधी की हत्या करवा दी गई । गुप्त रूप से इस हत्या का लान्छन इंदिरा के चरित्र हनन से जोड़ दिया गया। कहा गया कि इंदिराबिलास की गुप्त रीलें संजय ने पकड़ ली थी इसी भय से इंदिरा ने अपने ही बेटे की हत्या करवा दी । देश से विदश तक षड्यंत्रो के जाल राजनीति के ताल में फेंके जाने लगें। पूर्व पाकिस्तान के नाम पर अमरीका का साथ ले कर भारत से छल युद्ध। यहियाखॉ दहाड़े हमारा सामना भारत की एक मक्कार औरत से है। अटल ने कहा भारत में दुर्गा का अवतार हो चुका है । भुट्टो ने कहा –भारत से हम चौदह सौ बरस तक लड़ते रहेंगें । नतीजा चौदह दिन में ही। तिरान्नवे हजार पाकिस्तान फौज इंदिरा के कदमो में । यदि पाकिस्तान चौदह सौ वर्षो तक दुर्गा से युद्ध करता तो अंजाम खुदा ही जानता ।

अब पाकिस्तान ने तब के ओसामा बिन लादेन संतभिडरा वाले के इंदिरा के सामने भेज दिया। मुसलमान षड्यत्रो के माहिर माने जाते है । संत भिडरावाले के आगे आने से सारे सिख इंदिरा विराधी हो गए –गुरू गोलवलकर के देहावसान पर इंदिरा ने उन्हे श्रद्धांजलि दे दी थी –फलतः धर्मनिरपेक्ष कांग्रेसी हिन्दु आग बबूला हो गए। आर0एस0एस0 ने भी इंदिरा से दूरी बनाये रखी। गुरू गोलवलकर का पंचाधिकम् शतम् इंदिरा के कोइ काम न आ सका – कोई तपोनिष्ट आर्य समाजी कांग्रेस में शेष नही था। दुर्गा अकेली हो गई । महाभारत की द्रोपदी के बाद पदिमिनी का जौहर कुछ और भी नाम मिल सकते है परंतु इन सब में इंदिरा मात्र एक नाम है जो अपने ही रक्षक द्वारा नोच डाली गई। उसे हिदूं नारी होने की भरपूर सजा दी गई।

चौरासी के दंगे मे मै दिल्ली गया हुआ था –राजनीति के खिलाड़ी धर्मनिरपेक्ष हिन्दू नेताओ ने मुस्लिम रक्त पिपासुओ को ले कर सिख्खो की जिस प्रकार सामूहिक हत्याएं करवाई उससे पाकिस्तान के हिन्दू सिक्ख नर मेध का दृष्य एक बार पुनः देखने मे आया । इंदिरा ने भारत बचाया। भारतीय निष्ठा स्वर्ण मंदिर की पवित्रता बचाई। उफ भारत इंदिरा ओर भारतीयता को नही बचा पाया। अब वर्तमान परिवेशः। लेख के डेढ़ मीटर शरीर को ढकने के लिए हमने पॉच मीटर भूमिका की साड़ी बना डाली क्षमा प्रार्थी हूँ।

श्रद्धेय मुनि जी ! आप सभवतः हिन्दुओ के अनेक संगठनो से संबंधित या परिचित रहे है। आर्यसमाज से सर्वोदय से आर0एस0एस0 से कांग्रेस से भी शायद रहे हो । परंतु किसी समाज में जुड़ कर नही रह सके। किसी सिद्धान्त से चरित्र से नीति से सदैव समाज से उपर माना । वर्तमान परिवेश में आप स्वयं कहते है कि पूरे भारत में आप अभी अकेले व्यक्ति है जो मनमोहन सिंह को ईमानदार, नेक, भला और कमजोर प्रधान मंत्री मानता है। वही सरलता की मूरत जिसने शासन के प्रत्येक भ्रष्टाचारी को अंत तक क्लीन चिट दिया और अभी भी धृतराष्ट की शानदार भूमिका निभाता जा रहा है। वही जिसने चौरासी के दंगो के लिए कांग्रेस की ओर से सिक्खो से क्षमा मांगी है। सिक्खो से कोई छल नही ईमानदार माफी।

मनमोहन सिंह ने भारत के प्रत्येक संसाधन पर मुसलमानो के प्रथम अधिकार की घोषणा की है–वहीं कश्मीरी पंडितों की जान माल की रक्षा का संकेत तक नहीं दिया है–ईमानदार आदमी गलत वादा नही करता । ईमानदार पी0एम0 ने पहले अधिकारी की घोषणा कर दी परंतु दूसरा अधिकारी कौन होगा जानना हो तो प्रतिक्षा करें । मुनि जी आप स्वामी अग्निवेष जी राजनीतिक आर्य सन्यासी योग गुरू रामदेव जी सुषमा जी मोदी जी के प्रमुख आलोचक हैं तथा एक लंबे अरसे से मनमोहन जी की तेल मालिश कर रहें हैं और मन मोहन को पवित्रता ईमानदारी का सर्टिफिकेट थोक भाव में दे रहें है । आप ने सुषमा जी को मशविरा दे डाला कि वे संसद वालो की ईमानदारी या भ्रष्टाचार न देंखे। उन्हें चाहिए कि नक्सलवादियो का हल करें । मैने भी इस प्रसंग पर विचार किया। निष्कर्ष यह रहा । सुषमा जी को नक्सलवाद की समस्या उद्देश्य स्थान आदि का वास्तविक ज्ञान नही है ।परंतु आप में है ।2–दिग्विजय जी तो उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री रह चुके है। सोनिया जी के प्रिय पात्र आप की दृष्टि से दूर नही 3– सोनिया जी इंदिरा जी की प्यारी बहू है उन्हे बहुत बडा उत्तर दायित्व निभाना पड़ सकता है । 4–मनमोहन जी बहुत सीधे सज्जन एवं दूर्बल पी0एम0 है ये सभी भारत की सरकार है 5– भारत के गृह मंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है कि देश की आंतरिक व बाह्य समस्याओ को सुलझाते रहे । इसके पश्चात् हमारे ईमानदार पी0एम0 की प्रिय भ्रष्टाचारी टीम को भी देश सेवा का अवसर मिलना चाहिए। मेरा अनुमान है कि सुषमा का माओवाद तथा नक्सलवाद का ज्ञान आप लोगो की तुलना में कम है। अतःइस बार आप से अधिक योग्य टीम अन्य किसी दल के पास नही है । इस समस्या को सुलझा कर आप एक छोटा सा स्वच्छ इतिहास रचकर पुण्य के भागीदार बने ।

सुषमा जी को भ्रष्टाचारियो से भिंड़े रहने दें वे केवल आस्था की बाजीगिरी करती रहेंगी । भ्रष्टाचारियो का कुछ नही बिगड़ेगा। संसद की भी चिंता न करें । अरे वहॉ तो केवल कुर्सी मेज माइक तोड़ने वाले जूते खाने और जूते चलाने वाले ही रहते है–संसद में लगभग चौथाई सदस्य विदेश विभाग संभाल लेंगें वे सभी पाकिस्तानी भारतीय हैं। निश्चित रहिये दिल्ली पूरी तरह सुरक्षित है। आप तो बस मनमोहन एंड कंपनी और अधिक सहायता की आवश्यकता हो तो पासवान जी को बुला लें जो ओसामाबिन लादेन का चित्र भगवान के चित्र की भांति गले मे लटकाये घूमता था । अरे मुनि जी धृष्ट्रराष्ट्र के ऑखे नही थी परंतु मन मोहन जी के है। शरीर भी है शासन भी है आपके मतानुसार वे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। आपको अपनी बात पुष्ट सिद्ध करने का सुन्दर तम अवसर है–आप इनको साथ लेकर नक्सलियो के पास चले जाइये आप के नेतृत्व में यह छोटी सी नक्सल समस्या मिनटो में सुलझ जायगी ।

1:–आप का पूर्व में भी अपना मत रहा है'–संघ और भाजपा सत्ता लोभी है इनसे देश का हित संभव नही है।

2:–आप के ज्ञान तत्व में भी है 217 अंक दुनिया जानती है कि पी0 एम0 पूरी तरह ईमानदार है। मनमोहन जी को आपके अतिरिक्त पूरा भारत शंका की दृष्टि से देखता है

3:–भारत के अधिकारी केवल मुसलमान है।

4:–मोदी आप की निगाह में चढ़े हुए है । किस दिन आप लोग उन्हे जहन्नूम भेज दें कहा नही जा सकता । ऐसी अवस्था में आप सुषमा संघ भाजपा आदि से नक्सल समस्या के हल की अपेक्षा क्यों रखते है ।

आपने लिखा है कि कमजोर प्रधानमंत्री न होता तो विपक्षी इतना नही उछलते। मेंरी प्रतिकिया कमजोर की बहू सबकी भौजाई कहलाती है। जिस घर का मुखिया कमजोर होता है उस घर में सब का आना जाना होता है। जिस देश का राजा लोभी या कमजोर होता है वह देश नष्ट हो जाता है।अभी तो आप की धाराणानुसार एक दिन ये सभी दूध के धुले हुए सिद्ध होगे । मेरी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी दृष्टि के समस्त अपराधो जो अभी तक आप को छोड़ कर और सभी को निकृष्ट और घिनौने दिखते है वे आगे चल कर किसी दिन आपको कल्पना क अनुरूप वास्तव में देवता स्वरूप सिद्ध हो। ऐसी कामना मै आपके प्रति श्रद्धा के कारण नही कर रहा हूँ । बल्कि देश हित इसी में है कि हमारे सभी अगुआ ईमानदार सज्जन चरित्रवान निष्ठालु और विश्वसनीय भी हों । इन

लोगो की वर्तमान छवि अभी तक जो मेरी निगाह में है। वह एक दम गलत निकले भारत की स्वच्छ छवि के ये सुपात्र देश के गर्व का कारण सिद्ध हो और मै मुक्त कंठ से आप की दूर दृष्टि की विराटता का दर्शन करके आप को नमन करू ।
आप भी सारे हिन्दूओ को अपने दुराग्रह का शिकार न बनाये । संभव है कि हिन्दुओ में भी मानव सभ्यता के प्रेमी देश प्रेमी राष्ट्र प्रेमी सज्जन पुरूष भी हो। मेरे विचार से भाजपा और संघ में उतने बुरे लोग भी नही हैं जितना आप समझते है । मै पूर्व भी आप से लड़ता रहा हूँ। परंतु आप का स्नेह मिलता है ।इस बार तो पत्र से युद्ध ही कर बैठा हूँ। परंतु आप अपने प्रेम का अधिकार मुझ से नही छीनेंगे इस विश्वास के साथ–

उत्तर–आपका लम्बा पत्र मिला जिसका तीन चौथाई भाग मैने प्रकाशित कर दिया । आपने लेख में विचारों की ईमानदार समीक्षा की है। मुझे खुशी हुई । ऐतिहासिक घटनाओ के संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि संभव है कि कई बातें सत्य भी हों और कई बातें मनगढ़त भी हो सकती है। जिन घटनाओ को प्रमाणित करना न मेरे लिये संभव है न आपके लिये उनकी चर्चा छोड़ रहा हूँ। हो सकता है किन्ही बातो पर आपकी जानकारी अधूरी हो अथवा मेंरी जानकारी अधूरी हो । फिर भी मैं वर्तमान चर्चा के अतिरिक्त दो तीन बातें कहना चाहता हूँ।
1–मैं जीवन में कभी कांग्रेसी नही रहा । राजनैतिक जीवन मे प्रारंभ समाजवादी पार्टी से हुआ तथा बाद में अन्त तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहा ।
2–मुझे प्रारंभ में भी हिन्दु होने पर गर्व था और अब भी है। मै वैचारिक आधार पर हिन्दुत्व का प्रबल समर्थक हूँ । मै वैचारिक आधार के हिन्दुत्व को पहचान वाले हिन्दुत्व से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ ।
3 आपातकाल में सुव्यवस्था इन्दिरा जी का कमाल न होकर तानशाही का परिणाम था। मैने कई बार लिखा है कि जहॉ भी तानाशाही होगी वहॉ सुव्यवस्था होना निश्चित है। यह एक निश्चित सिद्धान्त है।
4– मैने जो बार बार दो सूचियॉ प्रकाशित की हैं उनमें प्रधानमंत्री के योग्य तेरह नाम है जिनमे नरेन्द्र मोदी रमण सिंह, नीतिश कुमार भी शामिल है । समस्या पैदा करने वालों की जो सूची प्रकाशित की है उन तेरह लोगो में रामबिलास पासवान और दिग्विजय सिंह भी है।
5. मै नक्सलवाद को भ्रष्टाचार से भी ज्यादा गंभीर समस्या मानता हूँ । मेरे विचार मे दिग्विजय सिंह राहुल गांधी, की टीम ने नक्सलवाद के समाधान मे हमेशा रोडे अटकाये है। मै समझता हू कि यह टीम भ्रष्टाचार का भी समाधान नही होने देगी।

वर्तमान राजनैतिक संदर्भ में मेरा मानना है कि मनमोहन सिंह को बदनाम करके राहुल गांधी को स्थापित करने का जो प्रयत्न चल रहा है वह खतरनाक है। नेहरू परिवार के ही व्यक्ति को इस पद के लिये तैयार किया जाय और ऐसे प्रयत्न सार्वजनिक रूप से हों और ऐसे प्रयत्नो का खुला विरोध न हो यह मैं गलत मानता हूँ। यदि मनमोहन सिंह कठपुतली हैं तो कठपुतली को भ्रष्ट कहने के पींछे क्या कारण है क्या स्वार्थ है? यदि आपको ज्ञान नहीं होता कि यह कठपुतली किसी अन्य द्वारा संचालित है तब तो अलग बात है। किन्तु सारी बात जानते हुए भी मनमोहन सिंह का प्रत्यक्ष विरोंध परोक्ष रूप से नेहरू वंश के राजकुमार का समर्थन है और मैं ऐसे अप्रत्यक्ष प्रयत्नो के खिलाफ हूँ। आप भले ही मेरे प्रयत्नो को गलत मानते है किन्तु मेरे प्रयत्न परोक्ष न होकर प्रत्यक्ष है।

मनमोहन सिंह सहित तेरह लोगों की प्रशंसा और रामबिलास पासवान सहित तेरह लोंगो की आलोचना मेरी तात्कालिक योजना है।सुषमा जी मेरे आकलन मे दोनो ही टीमो मे न होकर बीच के लोगों मे मानता हूँ । किन्तु मै सुषमा जी अडवानो जी, की अपेक्षा नरेन्द्र मोदी नीतिश कुमार का अधिक प्रसंशक हूँ । ज्योंही राहुल गांधी की तलवार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लटकाने की कोशिश बन्द हो जायगी तथा प्रधान मंत्री पद के लिये प्रतिस्पर्धा में नरेन्द्र मोदी नीतिश कुमार आदि मनमोहन सिंह के सामने दिखने लगगें त्योंही मेंरी यह तात्कालिक प्रशंसा योजना अनावश्यक हो जायगी क्योंकि भारत की वर्तमान समस्याओं का यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है । मै मनमोहन सिंह को अच्छा प्रधान मंत्री नही कह रहा । मै तो मात्र इतना ही कह रहॉ हूँ कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत मे परिवार वाद से हटकर लोकतंत्र की लाइन मजबूत हो रही है। मेरे विचार में भारत की समस्याओ का दीर्घकालिक समाधान तो सहभागी लोकतंत्र या लोक स्वराज्य ही है जिस आंदोलन की शुरूआत अन्ना जी कर रहें है। मैं पूरी तरह अन्ना हजारे के लोक स्वराज्य आंदोलन के साथ हूँ। आप ज्ञान तत्व अंक दो सौ चौबीस पचीस में पढ़े भी होंगे ही ।

3 श्री ओमपाल जी मेरठ उत्तर प्रदेश

प्रश्न 1 ज्ञान तत्व दो सौ तेइस में आपने आतंकवाद के तीन चेहरो में इस्लाम साम्यवाद के साथ साथ संघ परिवार का भी नाम शामिल किया है । इस्लाम हिंसा को आधार बनाकर दारूल इस्लाम कायम करना चाहता है तथाा साम्यवाद उसी आधार पर विश्व विजय करना चाहता है । किन्तु संघ का हिंसा के पीछे छिपा हुआ क्या उद्देश्य हो सकता है?
2–ऐसा सुना है कि आपके परिवार के लोग भी संघ परिवार के साथ जुड़े है । क्या आपकें अनुसार वे भी आतंकवादी है?
3–ज्ञान यज्ञ परिवार में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले बड़ी संख्या में संघ परिवार से जुड़े है। क्या आपके उनके किसी कार्य से आतंकवाद की गंध आती है?
4–जिस तरह विश्व के विभिन्न देशों में इस्लामिक या साम्यावादी आतंकवादी भूमिगत प्रशिक्षण केन्द्र चलाते है उसी तरह क्या संघ भी कभी करता है?
उत्तर–आपके चारों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े है। मैने न इस्लाम को आतंकवाद के साथ जोड़ा है न साम्यवाद को और न ही संघ परिवार को। मैने ज्ञानतत्व दो सौ तेइस में लिखा है कि आतंकवादी तत्व इन में से किसी एक को ढाल बनाकर उनको ओट में छिपने की कोशिश करते है। ये तीनो ही दूर दूर तक आतंकवादी नही है। आतंकवादी और उग्रवाद में बहुत अन्तर हैं। आतंकवाद जैसा कहता है वैसा ही करता है किन्तु उग्रवाद जैसा कहता है वैसा करता नहीं।संघ परिवार के लोग आमतौर पर समाज में हिंसा की आवश्यकता तो बताते हैं किंन्तु स्वयं वैसा नहीं करतें ।कोई संघ परिवार का सदस्य स्वयं बम फेंकता हेा ऐसा नहीं दिखता न ही वह कभी ऐसी घटनाओ में अन्दर से शामिल रहता है। पहली बार इन्द्रेश जी का नाम इस तरह आ रहा है अन्यथा आम तौर पर ऐसा नही होता । किन्तु संघ परिवार के लोग आमतौर पर सामाजिक हिंसा की आवश्यकता का समर्थन करते है जो उग्रवाद है । उग्रवाद भी कोई अच्छी बात नही क्योकि उग्रवाद बढ़ते बढते आतंकवाद की लाइन पकड़ लेता है । उग्रवाद तथा आतंकवाद के बीच एक पतली सी सीमा रेखा होती है। संगठन प्रायः सीमा रेखा का उलंघन नही करता किन्तु जब संगठन से जुडा कोई व्यक्ति इस सीमा का उल्लंखन करता है तब संगठन पर आंच आती है। आंच से बचने के लिये यदि सीमा रेखा से पर्याप्त दूरी बनाकर रखी जाय तो बुरी बात नही । उग्रवाद प्रायः हमेशा ही लाभ में रहा है। आज समाज में समस्याओ की जड़ में गांधीवादियों की बिल्कुल

विपरीत लाइन है। गांधीवादी एक ओर तो अहिंसा के नाम पर कायरता फैलाते रहते है तो दूसरी ओर व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर इस्लामिक आतंकवाद अथवा नक्सलवाद तक का परोक्ष समर्थन करतें है। ध्यान रहे कि जब समाज में कायरता ह तब उग्रवाद का उपयोग बहुत लाभदायक होता है। ऐसा लाभ स्वतंत्रता के बाद इस्लाम को भी मिला और साम्यवाद को भी और उसी को देख देख कर संघ परिवार भी उस लाइन पर चल पड़ा । वर्तमान समय मे इन तीनो ही संगठनो को आतंकवाद से जूझना पड़ रहा है । समाज में आतंकवाद के विरूद्ध तो वातावरण बन ही रहा है उग्रवाद के भी विरूद्ध बन रहा है। गंभीरता पूर्वक विचार करिये कि पूरी दुनिया के मुस्लिम देश किस संकट से जूझ रहे है। आज हिन्दुओ मे भी आतंकवाद जड़ जमा लेता तो वह संघ परिवार के लिये ही नासूर बनता । अब विश्व मे हिसा के प्रति विरोध बढ़ रहा है। संभव है कि लाभ की जगह हानि हो जावे। मै पूरी तरह गांधी का समर्थक हूॅ और कायरता का विरोधी । मै डा0 हेडगेवार का समर्थक हूॅ जिन्होने दलगत राजनीति से दूर रहकर राजनीति पर नियंत्रण की आवश्यकता बताई थी।किन्तु मै हेडगेवार का नाम लेकर राजनीति करने वाले वर्तमान संघ चरित्र का पूरी तरह विरोधी हूॅ।

ज्ञान यज्ञ परिवार की निश्चत सीमाएं है। वह किसी भी प्रकार की किया से दूर सिर्फ विचार मंथन तक सीमित है। यदि हमारा कोई साथी हिंसा करता है तो हम उसे नहीं रोकते क्योंकि हिंसा का सहयोग या विरोध हमारा काम नही । हमारे साथ हिंसा समर्थक भी है और विरोधी भी । ज्ञान यज्ञ परिवार तो विचार मंथन का मंच मात्र है। मैं अहिंसा का समर्थक हूॅ । इसका यह अर्थ नही कि ज्ञान यज्ञ परिवार के अन्य साथी मुझसे जुड़े है। सबकी स्वंतत्र सोच है और स्वतंत्र संगठन है । हमारा कोई साथी विचार मंथन में भी स्वतंत्र है और क्रिया में भी । यदि हमारा कोई साथी किसी को गोली मारने के लिये मुझसे सलाह लेता है तो मै उसे उस किया से रोकूगा नही। मैं उस क्रिया की गलत सही परिणाम की व्याख्या तक सीमित हूॅ । इसलिए मेरे परिवार के सदस्य संघ के साथ भी जुड़े है और हमें कोई कठिनाई नही। संघ कोई उग्रवादियों का संगठन मात्र तो है नही । संघ परिवार में अनेक अच्छाईयो और बुराइयो का पृथक पृथक आकलन है । उसकें बाद सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है।

संघ परिवार की तुलना आतंकवादी संगठनो से नही की जा सकती । क्योंकि संघ परिवार न कही ऐसे प्रशिक्षण में संलग्न है न गतिविधियो में । किंतु संघ परिवार की तुलना गायत्री परिवार जैसी संस्थाओं से भी संभव नही । यहॉ तक कि स्वतंत्रता के पूर्व आर्य समाज के भी अनेक कार्यकर्ता हिंसा में संलग्न रह। स्वंतत्रता के बाद भी आर्य समाज कभी कायरता का पोषक नही रहा ।फिर भी आर्यसमाज पर कभी उग्रवादी संगठन का आरोप नही लगा । सोचना मुझे नही । संघ परिवार को है कि आज हिन्दू समाज में ही उसकी विश्वसनीयता घट क्यों रही है। मेरा काम यह समझना नही है । चूंकि मुझे संघ परिवार से बहुत उम्मीदें रही है । अन्यथा शायद मेरे परिवार के लोगो का इतना ज्यादा जुडाव संघ परिवार से नही होता । यही कारण है कि मैं संघ परिवार की व्यापक समीक्षा करता हूॅ। मुझे महसूस हेाता है कि लोगो को व्यक्ति रूप से सेाचना चाहिये कि हम आंख मूंदकर संघ परिवार की पुरानी लाइन पर ही चलते रहें अथवा संघ परिवार पर संशोधन के लिये दबाव बनायें ।

आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं संघ परिवार की नीतियों के पूरी तरह पक्ष में हूॅ। किन्तु कार्यप्रणाली कभी सफल नहीं हो सकती चाहें हम कितना भी जोर लगा लें और कितने भी वर्ष बिता दें । उस समय संघ परिवार मानता था कि बस दों चार वर्ष मे ही वह सब ठीक कर लेगा। तीस चालीस वर्ष बाद अब दों चार वर्ष की जगह दस पांच वर्ष कहा जाने लगा हैं। मैने तेा सेाच लिया है कि संशोधन हेतु दबाव बनना चाहिये । आप अपना निर्णय करने हेतु स्वतंत्र है।

4 आचार्य पंकज रिषिकेश उत्तराखंड

विचार – आप राममोहन राय के विषय मे लिखते रहे है । मेरी जानकारी अनुसार सती प्रथा को लेकर बंगाल उस समय दो गुटो मे विभक्त था। एक गुट के नेता थे प0 राधाकांत शास्त्री जी परम्परागत कहर हिन्दू वैदिक कर्मकाण्डी रूढिवादी थे तथा सतीप्रथा के प्रबल समर्थक थे । दूसरा राममोहन राय ब्रहम समाज मूर्तिपूजा विरोधी तथा सती प्रथा समाप्ति के लिये जन साधारण मे घूम घूम कर सभाये, गोष्ठी, बैठक करते हुए बडा जनान्दोलन खडा किया था। श्मशान घाटो पर जाकर चीता पर बैठाई गई विधवाओ को सती कराने वालो को सीधे रोकना संघर्ष पूर्ण कार्य था, कहरपंथियों से श्मशानो पर राममोहन राय की सीधी मुठभेड हुई , अकेले ही राममोहन राय चिता नही जलने देते थे उनकी माता जी ने धर्मविरोधी मानकर राममोहन राय को गृह प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था कहरपंथियो ने राममोहन राय कई बार प्राणघात हमले भी किये उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया, वे अपने अभियान मे जनान्दोलन के मध्य चट्टान की तरह खडे रहे । प्राणघातक हमलो के बावजूद भी राममोहन राय ने अंग्रेजी सरकार से अपनी सुरक्षा के लिये कोई गुहार नही जगाई । जन समर्थन उनका सुरक्षा कवच था। बंगाल के उस समय के अधिकारियो ने जो अंग्रेज थे सती प्रथा विरोधी जनान्दोलन को समाप्त करने के लिये कलकत्ते मे राममोहन राय तथा आन्दोलन के प्रबल विरोधी प0 राधाकांन्त शास्त्री को बैठक के लिये बुलाया । जब राधा कान्त एण्ड कम्पनी को पता चला कि अंग्रेजो ने राममोहन रय को भी बुलाया है तब उन लोगे ने इस बैठक के बहिष्कार की घोषणा के साथ नाश्तिक धर्मविरोधी राममोहन राय को गिरफतार कर सती प्रथा को जारी रखने की मांग की । अन्ततः ब्रहमसमाज का सतीप्रथा विरोधी जनान्दोलन व्यापक स्तर पर तेज हुआ। बंगाल की अंग्रेजी हूकूमत ने सतीप्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प0 राधाकान्त शास्त्री ने इस ब्रहम समाज की जीत मानकर, विलायत इगलैड जाकर प्रिवी कौन्सिल मे बंगाल की अंग्रेजी हूकूमत के आदेशों का चुनौती दी। प्रिवी कौन्सिल ने बंगाल के अंग्रेजी हूकूमत के आदेश को जायज ठहराते हुये प0 राधाकान्त शास्त्री की अपील खारिज कर दी। राममोहन राय के ब्रहम समाज के जन आंदोलन के कारण ही घोर अमानवीय सती प्रथा का समापन हो पाया

उत्तर– मै आंशिक जानकारी के आधार पर मानता था कि राममोहन राय ने जन जागरण न करके सरकार से सती प्रथा के विरूद्ध कानून बनवा दिया । किन्तु आपके अनुसार राजा राम मोहनराय ने सती प्रथा के विरूद्ध जनमत जागरण किया जिसे देख कर सरकार ने कानून बनाया । इस तरह राममोहन राय गलत नही थें। आपने इस संबंध मे जानकारी देकर बहत अच्छा किया है। आपसे निवेदन है कि इसी तरह अन्य विषयो पर भी मेरी जानकारी को ठीक करते रहियेगा।